एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			ए. आर. बी. ए. पी. सं. 60 सन 2023 **<u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.</u>** श्री विकास बहुगुणा, आवेदक के विद्वान वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 2. श्री वी. के. कप्रुवान, भारत संघ/प्रत्यर्थीगण के लिए स्थायी वकील। 3. यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन है। 4. आवेदक को ***"NH58 (नया NH-07) (बेनाकुली मोड़ से माना गाँव) के मौजूदा चेनेज किमी. 509.725 से किमी. 528.00 (डिजाइन चेनेज किमी. 90.550 से किमी. 507.850) तक पेव्ड शोल्डर वाली 2-लेन वाली मौजूदा सड़क के निर्माण और उन्नयन के लिए उत्तराखंड राज्य में चारधाम कार्यक्रम के अंतर्गत ईपीसी मोड में (लंबाई-17.30 किमी.)"*** एक अनुबंध दिया गया था। 5. आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच हुए इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण समझौता (संक्षेप में 'ईपीसी') आवेदन के साथ संलग्न है। 6. पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और 16.03.2023 को आवेदक द्वारा सुलह कार्यवाही शुरू करने के लिए ईपीसी के खंड 26.2 के संदर्भ में प्रतिवादी को नोटिस दिया गया। इसके बाद, आवेदक ने 19.06.2023 को ईपीसी के खंड 26.3 के संदर्भ में एक और नोटिस जारी किया, जिसके तहत उन्होंने श्री क्रांति

			कुमार गुप्ता, हाउस नंबर 470, सेक्टर 8, पंचकुला, हरियाणा को अनसुलझे विवाद को तय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रतिवादी से सहमति मांगी। 7. चूंकि उत्तरदाताओं ने आवेदक द्वारा जारी उपरोक्त किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए, आवेदक ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है। 8. प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है. उक्त प्रतिशपथ पत्र का पैराग्राफ नं. 5 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: ***"5. मध्यस्थता आवेदन के पैरा 7 की सामग्री के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि 19 जून 2023 के ईपीसी अनुबंध समझौते के खंड 26.3 को लागू करने वाला नोटिस सीधे इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। अनुबंध समझौते में मध्यस्थता खंड 26.3 के अनुसार, जो विवाद सुलह द्वारा नहीं सुलझाए जाते हैं, जैसा कि खंड 26.2 में प्रदान किया गया है, उन्हें सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (एसएआरओडी) के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। इस संबंध में ईपीसी अनुबंध दस्तावेजों की धारा संख्या 26.3 मध्यस्थता नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:*** ***26.3 मध्यस्थता*** ***(i) कोई भी विवाद जो सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, जैसा कि खंड 26.2 में प्रदान किया गया है, अंततः सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (एसएआरओडी) के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा।*** ***(ii) विवादों की मध्यस्थता के मामले में पक्ष***

			स्पष्ट रूप से निम्नानुसार सहमत हैं: *(क) 50 लाख रुपये (पचास लाख रुपये) तक के दावे मूल्य वाले विवाद के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होगी। प्राधिकरण के इंजीनियर ऐसे विवाद की स्थिति में तर्कसंगत निर्णय देंगे और वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।* *(ख) 50 लाख रुपये (पचास लाख रुपये) से ऊपर, लेकिन 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) तक के दावा मूल्य वाले विवाद के मामले में, इसे एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। प्राधिकरण 30 (तीस) दिनों के भीतर SAROD (विवादों के किफायती समाधान के लिए सोसायटी) द्वारा बनाए गए मध्यस्थों की सूची से 5 (पांच) मध्यस्थों के नाम प्रस्तावित करेगा और ठेकेदार 30 (तीस) दिनों के भीतर पांच की सूची में से एक नाम का चयन करेगा और ठेकेदार द्वारा चुना गया नाम विवाद वाले मामले के लिए एकमात्र मध्यस्थ होगा। यदि प्राधिकरण 5 (पांच) नामों की सूची प्रदान करने में देरी करता है, तो अध्यक्ष, एस. ए. आर. ओ. डी. इस संबंध में पीड़ित पक्ष से संदर्भ प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर 5 नाम प्रदान करेंगे। यदि ठेकेदार पांच की सूची में से एक का चयन करने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष, एसएआरओडी इस संबंध में पीड़ित पक्ष से संदर्भ प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई पांच की सूची में से एक का चयन करेगा।* *(ग) 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) से अधिक के दावे मूल्य वाले विवाद के मामले में, इसे 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। विवाद का निपटारा सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (SAROD) के मध्यस्थता नियमों के अनुसार किया जाएगा।* *(घ) मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा, और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।* *ङ) मध्यस्थों की फीस प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होगी।*

			मध्यस्थता की लागत पक्षों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी। *(च) कोई भी पक्ष किसी पूर्व-संदर्भ और पेंडेंट लाइट ब्याज का हकदार नहीं होगा, यानी, ब्याज कार्रवाई की तारीख से मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की तारीख तक । पार्टियां विशेष रूप से सहमत हैं कि ऐसे किसी भी हित के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और वह अमान्य होगा। मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास विवादों के मामले में पूर्व संदर्भ या वादकालीन ब्याज देने की कोई शक्ति/क्षेत्राधिकार नहीं होगा।* *(iii) मध्यस्थ एक तर्कसंगत निर्णय ("अवार्ड") देंगे। इस अनुच्छेद 26 के अनुसार आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट, उसके दिए जाने की तारीख से पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, और ठेकेदार और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट को पूरा करने के लिए सहमत होते हैं और वचन देते हैं।* *(iv) ठेकेदार और प्राधिकरण इस बात पर सहमत हैं कि ठेकेदार और/या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, और उनकी संबंधित संपत्ति, जहां भी स्थित हो, के खिलाफ एक पंचाट लागू किया जा सकता है।* *(v) यह समझौता और पार्टियों के अधिकार और दायित्व यहां किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लंबित होने तक पूरी ताकत और प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा, पार्टियां बिना शर्त स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि उनके बीच किसी भी विवाद के बावजूद, प्रत्येक पार्टी इस अनुच्छेद के अनुसार विवाद के समाधान तक अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन के साथ आगे बढ़ेगी।* *(vi) यदि जिस पक्ष के खिलाफ पंचाट दिया गया है, वह किसी भी कारण से अदालत में पंचाट को चुनौती देता है, तो उसे पंचाट के 75% (पहत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए*

			दूसरे पक्ष को अंतरिम भुगतान करना होगा, विवाद का अंतिम निपटारा लंबित है। उपरोक्त राशि का 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उपरोक्त राशि का भुगतान तुरंत किया जाएगा। विवाद के अंतिम निपटारे पर, उपरोक्त अंतरिम भुगतान को समायोजित किया जाएगा और भुगतान की जाने वाली या वापस की जाने वाली शेष राशि, जैसा भी मामला हो, 10% (दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से गणना की गई ब्याज के साथ भुगतान या वापस की जाएगी, अंतरिम भुगतान की तारीख से ऐसे शेष के अंतिम निपटान की तारीख तक। " ***खंड संख्या 26.3 (i) के प्रावधान के अनुसार विवाद को विवादों के किफायती समाधान के लिए सोसायटी (इसके बाद एसएआरओडी कहा जाएगा) के माध्यम से भेजा जाएगा, हालांकि वर्तमान मामले में, ईपीसी ठेकेदार ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सीधे इस कार्यालय से संपर्क किया है। तदनुसार, दिनांक 19.06.2023 के विषय नोटिस पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि नोटिस सीधे इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, न कि विवादों के किफायती समाधान के लिए सोसायटी (जिसे इसके बाद SAROD कहा जाएगा) के माध्यम से, जो अनुबंध समझौते के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता है।*** 9. ईपीसी के खंड 26.3 के संदर्भ में कार्य न करने के लिए जवाबी हलफनामे के पैरा संख्या 7 में लिया गया रुख यह है कि आवेदक ने सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रिजॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स (एसएआरओडी) से संपर्क किए बिना, सीधे प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय को नोटिस दिया था। जब उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से पूछा गया कि क्या ईपीसी के तहत कोई खंड है, जिसके लिए ठेकेदार को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस देने से पहले विवादों के किफायती

			समाधान के लिए सोसायटी से संपर्क करना होगा, तो श्री वी. के. काप्रुवान का जवाब नकारात्मक थे, क्योंकि वह ईपीसी में ऐसे किसी खंड का उल्लेख नहीं कर सके। उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया खंड स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि एक विवाद जो सुलह द्वारा हल नहीं किया जाता है, उसे मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा और इसके अलावा मध्यस्थता की कार्यवाही विवादों के किफायती समाधान के लिए सोसायटी के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त खंड में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विवादों के किफायती समाधान के लिए सोसायटी को अनुरोध किया जाना चाहिए और यह केवल प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए उक्त सोसायटी द्वारा बनाए गए नियमों को अपनाता है। 10. इस प्रकार, मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रार्थना का विरोध करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 11. चूंकि एक बाध्यकारी समझौता था और समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड के मद्देनजर समझौते के पक्षों के बीच विवाद/मतभेद उत्पन्न हो गया है, ऐसे विवाद/मतभेद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। आवेदक ने विवाद के निपटारे के लिए समझौते का इस्तेमाल किया है, जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 12. तदनुसार मध्यस्थता आवेदन की अनुमति है । मैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.सी. पंत, (सेवानिवृत्त), जिनके पास मोबाइल नंबर 9412084455 है, को उनके उपरोक्त समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी विवादों, दावों और प्रति-दावों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में

			नियुक्त करता हूं। विद्वान मध्यस्थ कार्यवाही को वर्चूअली रूप से भी संचालित कर सकता है। **(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे)** 24.11.2023 नवीन